The Economic Times- 23-4-13

# लेवी शुगर बेचकर किसानों का बकाया चुका रहीं मिलें

[ श्रेया जय *नई दिल्ली* ]

**डीकंट्रोल के** बाद शुगर इंडस्ट्री इनवेस्टमेंट करने से पहले मार्केट का मूड भांप रही है। पहले शुगर कंपनियों को प्रोडक्शन का 10 फीसदी हिस्सा सरकार को कम कीमत पर बेचना पड़ता था। अब वे इसे ओपन मार्केट में बेच पाएंगी। शुगर कंपनियां इस पैसे से पहले किसानों का बकाया चुकाएंगी। कोलकाता की बलरामपुर चीनी मिल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक सरावगी ने बताया, 'हमने अभी तक कोई इनवेस्टमेंट प्लान नहीं बनाया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और गन्ने की कीमत जैसे मसले अभी नहीं सुलझे हैं। लेवी शुगर की पाबंदी हटना हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन इस पैसे को कहां लगाया जाए, इस पर काफी सोचने की जरूरत है।'

डीकंट्रोल के बाद मिलों को 10 फीसदी चीनी सरकार को कम कीमत पर नहीं बेचने पड़ेगी। केंद्र इसे राशन शॉप्स से गरीबों को कम दाम पर बेचता था। इससे मिलों को बड़ी राहत मिली है। वे अब इस चीनी को मार्केट प्राइस पर बेच पाएंगी। इससे उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन इस आधार पर इनवेस्टमेंट प्लान बनाना अभी ठीक नहीं होगा।

हालांकि, सरकार ने गन्ने की कीमत को चीनी के दाम से जोड़ने का एलान नहीं किया है। यह मामला राज्यों पर छोड़ दिया गया है। सरकार गन्ने के लिए जो कीमत तय करने की सलाह देती रही है, राज्य अक्सर उससे ज्यादा दाम तय करते रहे हैं। ऐसे में लॉस में चलने वाली मिलें किसानों के पेमेंट पर डिफॉल्ट करने को मजबूर होती हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर विनय कुमार ने बताया, 'शुगर मिलें अपनी पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। लेवी शुगर की पाबंदी और गन्ने की ज्यादा कीमत के चलते वे ऐसा नहीं कर पा रही थीं। ऐसे में अब लेवी शुगर को मार्केट में बेचने से जो पैसा आएगा, पहले वह किसानों को दिया जाएगा। कुछ महीने बाद ही मिलें इनवेस्टमेंट प्लान के बारे में सोचेंगी।'

> **हमने अभी तक कोई इनवेस्टमेंट प्लान नहीं बनाया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और गन्ने की कीमत जैसे मसले अभी नहीं सुलझे हैं। लेवी शुगर की पाबंदी हटना हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन इस पैसे को कहां लगाया जाए, इस पर काफी सोचने की जरूरत है**
>
> **विवेक सरावगी, बलरामपुर चीनी मिल्स के एमडी**

कुछ मार्केट्स में इस ट्रेंड की शुरुआत भी हो चुकी है। देश की बड़ी चीनी मंडियों में से एक कोल्हापुर में छोटी मिलें महाराष्ट्र और कनार्टक की मिलों को बल्क में चीनी बेच रही हैं। वे किसानों का बकाया पैसा चुकाने के लिए ऐसा कर रही हैं।